[अर्थ जगत]

विदेशी मुद्रा भंडार 1.14 अरब डॉलर घटकर 640.87 अरब डॉलर

मुंबई, 14 नवम्बर (अरब डॉलर घटकर 64 डॉलर बढ़कर 642.02 अनुसार, 05 नवंबर क परिसंपत्ति 88.1 करोड़ करोड़ डॉलर गिरकर 3

सीआईएबीसी ने बिहार सरकार को शराब पर प्रतिबंध खत्म करने को लेकर लिखा पत्र

- बिहार में शराबबंदी की भारी कीमत चुकाई जा रही
- अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री बढ़ी
- नीतीश कुमार सरकार ने अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की थी

राज्य में शराब प्रतिबंध ने शराब माफिया को जन्म दिया है। इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से राज्य में संभावित निवेश भी नहीं हो रहाः- विनोद गिरी, महानिदेशक, सीआईएबीसी

नई दिल्ली, 14 नवम्बर (देशबन्धु)। द कनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कम्पनीज (सीआईएबीसी) ने बिहार सरकार को एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने संबंधी पत्र लिखा है। सीआईएबीसी ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई ऐसे कदम भी सुझाएं हैं, जिनके माध्यम से प्रतिबंध हटाने के बाद बिना विवाद उपजे महिलाओं को कई तरह से सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

सीआईएबीसी ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल सभी दलों को पत्र में लिखा है कि बिहार में शराबबंदी की भारी कीमत चुकाई जा रही है। इसकी वजह से राज्य में एक ओर जहां अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री बढ़ रही है, वहीं अवैध शराब की वजह से कई तरह की दर्दनाक घटनाएं भी सामने आ रही है। इनके अलावा संगठित अपराध का विस्तार हो रहा है। जबकि सरकार को मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। बिहार राज्य की तरक्की और विकास इसकी वजह से लगातार प्रभावित हो रहा है। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब बिहार में मिलावटी शराब पीने की वजह से 4 जिलों में 40 व्यक्तियों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार सरकार ने अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की थी। उसके बाद से लगभग 150 लोग मिलावटी शराब पीने की वजह से अपनी जान गवा चुके हैं।

सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी के मुताबिक राज्य में शराब प्रतिबंध ने शराब माफिया को जन्म दिया है। इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से राज्य में संभावित निवेश भी नहीं हो रहा है। जिससे राज्य में शराब उद्योग के क्षेत्र में नई नौकरियों का सृजन भी बंद हो गया है। राज्य में शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राशि थी।राज्य में शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जिससे राज्य पर उधार लेने का दबाव भी बढ़ रहा है।